

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 154/25

GCMS NO 2025/288



भगवान गिरि चेला दौलत किशोर जाति गिरि गुसाई निवासी बदरी के हनुमान के पास करौली तहसील व जिला करौली

अपीलांत

बनाम

मूर्ति मंदिर जी श्रीमहादेव जी हनुमान जी विराजमान बदरी के हनुमान करौली तहसील व जिला करौली जरिये नेक्सट फ्रेण्ड एवं दर्शनार्थी

1. शिम्भू पुत्र अर्जुन जाति कहार निवासी तावे की टोरी करौली तहसील व जिला करौली
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र जमुना प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी तावे की टोरी करौली तहसील व जिला करौली
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील करौली

रेस्पो

(अपील विरुद्ध मु0नं0 60/10 निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.25 न्यायालय उप जिला कलक्टर, करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री रामनिवास पाराशर
अभिभाषक रेस्पो0 श्री विष्णु चंद बंसल

दिनांक 28.04.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय दिनांक 28.10.25 न्यायालय उप जिला कलक्टर, करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 व मन्जू पुत्र मांगी द्वारा एक वाद घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा एवं कायम किये जाने रिसीवर इस आशय का पेश किया कि आराजीयात खसरा न0 2539 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा , 2544 रकबा 13 विस्वा, 2545 रकबा 17 विस्वा, 2562 रकबा 6 विस्वा, 2563 रकबा 2 विस्वा, 2564 रकबा 5 बीघा 6 विस्वा, 3769 लगायत 3772 एवं 3774 एवं 3785 तथा 3786 व 3789 तथा 3790 कुल किता 15 कुल रकबा 11 बीघा 12 विस्वा स्थित करौली मंदिर मूर्ति महादेव जी व हनुमान जी स्थान बदरी के हनुमान कस्बा करौली पटवार हल्का 8 करौली स्थित है। यह आराजीयात मूर्ति मंदिर महादेव जी व हनुमानजी की खुद काश्त की खातेदारी व कब्जे की है। जिनके खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकार्ड आफ राईटस जमाबंदी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2015 मे दर्ज है। आराजीयात खसरा न0 2539,2544,2545,2562,2563,2564 कुल किता 6 कुल रकबा 8 बीघा 12 विस्वा दर्ज वाद पत्र मद न0 1 मूर्ति हनुमान कस्बा करौली मे है। यह आराजीयात मूर्ति मंदिर महोदव जी हनुमान जी की तन्हा खातेदारी व कब्जा काश्त की खुद काश्त भूमि सेवायत को व्यवस्थापक को कोई खातेदारी अधिकार मूर्ति मंदिर भूमि पुजारी व्यवस्थापक खातेदार नहीं हो सकता है। मूर्ति मंदिर खातेदार होता है मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है और शाश्वत नाबालिग की

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

खातेदारी भूमि पर पुजारी का सेवायत को अन्य किसी व्यक्ति को विधि अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं ना ही पुजारी ऐसी भूमिका विधि अनुसार खातेदार हो सकता है। यह प्रावधान धारा 46 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में स्पष्ट है। वाद पत्र के इस पैरा में दर्ज भूमि कृषि भूमि है। मूर्ति मंदिर भूमि जनहित की भूमि होती है जनहित के उद्देश्य के लिए भूमि होती है। पुजारी का सेवायत व्यवस्थापक मूर्ति मंदिर के प्राकृतिक संरक्षक भी नहीं है। वस्तुतः संरक्षक/डिफेक्टेड मार्जियन की स्थिति में होते हैं। देव मूर्ति मंदिर की खातेदारी की भूमि मूर्ति मंदिर की मिल्कियत की भूमि का प्राकृतिक संरक्षक द्वारा भी बिना जिला न्यायाधीश के न्यायालय के अनुमति के हस्तान्तरण नहीं होता है। बिना न्यायालय अनुमति को मंदिर भूमि का हस्तान्तरण अवैध होता है। यह विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था है। भूमि दर्ज वाद पत्र पैरा न0 2 मूर्ति मंदिर महादेव जी हनुमान जी की राग भोग व्यवस्था के लिए है एवं इस भूमि के हुए अनाधिकार, बिना आधार अवैध खातेदारी इन्द्राज बहक दौलतपुरी चेला शंकरपुरी जाति गुसाई निवासी कस्बा करौली प्रतिवादी न0 1 के हक में हुए है यह पूर्णतः विधि विरुद्ध है प्रभावहीन व शून्य है और हक हकूक खातेदारी मूर्ति मंदिर महादेव जी व हनुमान जी विराजमान बंदरी का हनुमान मौसूमा करौली प्रारंभतः प्रभावहीन व शून्य है। बाध्यकारी नहीं है विधि अनुसार पुजारी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया जा सकता है। पुजारी को मूर्ति मंदिर भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। राजस्व विभाग द्वारा ऐसे परिपत्र भी राजस्व कर्मियों को अधिकारियों को जारी किये हुए हैं वादी मूर्ति मंदिर महादेव जी व हनुमान जी विराजमान कस्बा करौली मौसूमा बंदरी का हनुमान दर्ज वाद पत्र पैरा न0 2 में दर्ज आराजीयात का अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है और वादी मूर्ति मंदिर महादेव जी हनुमान जी विराजमान कस्बा करौली के हक में राजस्व रिकार्ड आफ राईटस जमाबंदी में खातेदारी इन्द्राज कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी दौलतपुरी शंकरपुरी का विधिवत शिष्य नहीं है। प्रतिवादी कमलगिरी का जन्मदाता पुत्र है प्रतिवादी दौलतपुरी ने राजस्व कर्मियों से मिलकर बिना आधार अनाधिकार तौर पर वादी मंदिर मूर्ति की खातेदारी व कब्जे की भूमि के स्थान पर अपने हक में अवैध तौर पर बिना आधार खातेदारी इन्द्राज करा लिये है। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी दौलतगिरि मूर्ति मंदिर महादेव जी हनुमान जी का रक्षक नहीं होकर भक्षक बन गया है। राजस्व कार्मिक भी प्रतिवादी से साज कर गये हैं प्रतिवादी दौलतगिरि के हक में किया गया खातेदारी इन्द्राज पूर्ण रूप से राजस्व रिकार्ड से हटाये जाने योग्य है। वादी जो कि कस्बा करौली के निवासी है तथा मूर्ति मंदिर महादेव जी व हनुमान जी के दर्शनार्थी है और वादी मूर्ति मंदिर के नैक्सड फ्रेण्ड हितेषी है। दावा पेश करने के अधिकारी है। प्रतिवादी गलत इन्द्राज के आधार पर मूर्ति मंदिर की भूमि को बेचान करने पर आमादा है। जिसके बाबत प्रतिवादीगण ने बेचान की बातचीत कर ली है। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध भूमि बेचान नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में एल एन टी चलाकर सैकड़ों हरे वृक्षों को उखाड़ दिया है तथा भूमि में निर्माण करने पर आमादा है। वादी द्वारा प्रतिवादी से मना किया तो प्रतिवादी झगडा करने पर आमादा हो गया। पुजारी को मंदिर की भूमि को अपने नाम कराने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। मूर्ति मंदिर की भूमि पर कब्जे के आधार पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। प्रतिवादी न0 1 द्वारा अपने हक में कराया गया नामा0 व खातेदारी इन्द्राज पूर्णतया कपट पूर्ण है। जो विधि विरुद्ध है। प्रभावहीन व शून्य है जो निरस्त किये जाने योग्य है। वादी मूर्ति मंदिर को कोई नोटिस व सुनवाई का अवसर


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधापुर

प्रतिवादीगण द्वारा नहीं दिया गया है। वादी वाद पत्र के पैरा संख्या 2 में दर्ज आराजीयात की घोषणा अपने नाम कराने का अधिकारी है। भूमि मंदिर के खुदकाशत की है मंदिर हितों को ध्यान में रखते हुए जनहित में वादी मंदिर हित में वादग्रस्त आराजीयात पर रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायोचित है। वादग्रस्त आराजीयात के अलावा खसरा नं० 2539,2544,2545,2562,2563, 2564 फांचना सिचाई परियोजना डूब में चली गई है। जिसका मुआवजा भी प्रतिवादी नं० 1 मंदिर वादी को धोखा देकर कपटपूर्ण तरीके से स्वयं को खातेदार बताकर मुआवजा धन राशि प्राप्त कर ली है। जिसके लिए अलग से कार्यवाही की जावेगी। वाद पत्र केवल पैरा संख्या 2 में दर्ज भूमि के लिए पेश किया गया है। मंदिर की भूमि पर प्रतिवादी नं० 1 पूर्णतया अतिक्रमी की हैसियत से होने के कारण बिना अधिकार होने के कारण प्रतिवादी को भूमि से बेदखल किया जाना आवश्यक है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी मूर्ति मंदिर श्री महादेव जी व हनुमान जी स्थित कस्बा करौली तहसील करौली की आराजीयात दर्ज वाद पत्र पैरा संख्या 2 कुल किता 6 कुल रकबा 8 बीघा 12 विस्वा स्थित कस्बा करौली का खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर वादी के हक में राजस्व रिकार्ड आफ राईट्स जमाबंदी में वादी के नाम खातेदारी इन्द्राज किया जावे तथा प्रतिवादी नं० 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त आराजीयात को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करे तथा किसी प्रकार से पंजीयन नहीं करावे एवं आराजीयात में खड़े वृक्षों को किसी प्रकार से नहीं काटे ना ही उखाड़े तथा किसी प्रकार का निर्माण नहीं करे व प्रतिवादी का कब्जा अनाधिकार होने से प्रतिवादी को बेदखल किया जावे एवं न्याय दृष्टि से वादी मंदिर भूमि की सुरक्षा रख रखाव के लिए आवश्यक व उचित समझे जाने पर न्यायालय द्वारा रिसीवर नियुक्त किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/ रेस्पोंड संख्या 1 व 2 व मन्जू पुत्र मांगी द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांत/प्रतिवादी संख्या 1/1 के द्वारा यह अपील इस न्यायालय द्वारा पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंड को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की अपील पर सुनी गई।

अपीलांत के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, साक्ष्य व दस्तावेजात के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांत की तामिल रजिस्टर्ड डाक से उसे प्राप्त होना मानते हुए 1.10.25 को उसके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश जल्दबाजी में मनमाने तरीके से पारित करने में अहम भूल की है। जबकि पोस्ट में द्वारा उसे कोई न्यायालय के सम्मन की तामिल नहीं हुई है ना ही उसे जरिये डाक सम्मन आज दिवस तक प्राप्त हुआ है। पत्रावली पर भी ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। जिससे अपीलांत पर व्यक्तिगत रूप से तामिल उसे प्राप्त हुई हो। इन तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से तामिल मानते हुए एक पक्षीय कार्यवाही उसके विरुद्ध करके एक पक्षीय निर्णय वगैर साक्ष्य व सुनवाई का अवसर अपीलांत को दिये निर्णय जैर अपील पारित किया है। जो अपास्त किया जाकर मामला पुनः अधिनस्थ न्यायालय को अपीलांत की साक्ष्य सुनवाई किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाकर पुनः विधि अनुसार निस्तारण किये जाने के निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय को भिजवाया जाना


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

आवश्यक एवं न्यायोचित है। प्रकरण रिमाण्ड किया जावे। विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की रही है भूमि कभी भी मंदिर मूर्ति हुनमान जी महादेव जी की खुदकाश्त नहीं रही है। अपीलांट की विवादित भूमि को सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा वगैर किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के मंदिर के नाम सम्बत 2015 में की है। जो कतई नियम विरुद्ध गैर कानूनी होने से रेस्पों को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होत है। जागीर रिजम्पशन के दिवस विवादित भूमि मंदिर की खुदकाश्त नहीं रही है प्रकरण में अपीलांट के खातेदारी अधिकार का मामला निहित होने के कारण उन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के तहत साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। जिससे उसके हक की रक्षा हो सके इसलिए एक पक्षीय आदेश दिनांक 1.10.25 व निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.25 अपास्त किया जाकर मामला पुनःविधि अनुसार निस्तारण हेतु रिमाण्ड किया जाना जरूरी है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया कि सेटलमेंट पूर्व से कब्जा आज तक अपीलांट का विवादित भूमि पर चला आ रहा है। विवादित भूमि कभी भी मंदिर खुदकाश्त की नहीं रही है इसके बाबजूद उनके साधिकार कब्जे से भूमि छीनने के उद्देश्य से अपीलांट को बेदखल कर रेस्पों संख्या 3 को कमेटी बनाकर इन्तजाम काश्त के आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की है। निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों की अवहेलना कर अनदेखी की है। रिसेवर के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में धारा 212 के अनुसार रिसेवर ताफैसला दावा किया जाता है। जो मूल वाद के निस्तारण तक प्रभावशील रहता है। इस मूल वाद में रिसेवर की तरह आदेश पारित किया है जो विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। रेस्पों ना तो नेक्स्टफ्रेण्ड है ना ही दर्शनार्थी है। देशतापूर्णक दावा पेश किया गया है। मंदिर की सेवा पूजा दौलतगिरि करते थे उनकी मृत्यु पश्चात उनके द्वारा अपीलांट के हक में रजिस्टर्ड वसीयत करने के फलस्वरूप उनके जीवनकाल से अपीलांट काश्त करता रहा है तथा मृत्यु होने के उपरान्त आज तक सेवा पूजा राग भोग करता चला आ रहा है। मंदिर मूर्ति हनुमान जी व महादेव जी व विवादित भूमि पर कब्जा काश्त आज दिवस तक चला आ रहा है। और काबिज है। दौलतगिरि बनाम बालकृष्ण शर्मा के मध्य पूर्व में मुकदमे चले हैं उन्होंने रेस्पों शिम्भू कहार जो बालकृष्ण शर्मा के भाई ओपीनइयर एडो के यहाँ काम करता था उसके व भाई के लडके राजेन्द्र से यह दावा मंजू का नाम लिखकर दर्ज कराया है उनका इरादा येनकेन प्रकरण विवादित भूमि को हडपने का रहा है रेस्पों का उद्देश्य मंदिर के विपरीत रहा है इसलिए नेक्स्टफ्रेण्ड नहीं हो सकते हैं निर्णय एवं डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। दौलतपुरी बनाम बालकृष्ण दावा मुकदमा न0 71/85 न्यायालय ए डी एम करौली से दिनांक 16.4.86 को डिक्री हुआ है। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 20.11.25 को एक पक्षीय कार्यवाही व निर्णय व डिक्री की जानकारी देने पर अपीलांट को निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। इसलिए अपील जानकारी के आधार पर अन्दर मियाद पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.25 अपास्त फरमाया जाकर प्रकरण पुनः साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

रेस्पों के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड के अवलोकन के बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जबकि सत्यता यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सम्पूर्ण


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाकर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। इसी प्रकार अपीलांत अधिवक्ता का यह कथन भी मिथ्या है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को किसी प्रकार का कोई नोटिस भिजवाया है ना ही अनसी तामिल हुई है जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से नोटिस जारी कर अपीलांत को तलब किया गया है जिसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 अर्थात अपीलांत द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जबाब दावा पेश किया गया है। इससे अपीलांत का उक्त कथन स्वतः ही झूठा साबित होता है। इसी प्रकार अपीलांत अधिवक्ता का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलांत की खातेदारी की भूमि रही है, अपीलांत अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है क्योंकि वादग्रस्त आराजीयात मंदिर मूर्ति हनुमान जी, महादेव जी की खुदकाशत की भूमि रही है। सेटलेंट कर्मचारियों द्वारा कोई गलती नहीं की गई है। भूमि जागीर रिज्मशन के दिवस को मंदिर की खुदकाशत की भूमि रही है। अपीलांत अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि वादग्रस्त आराजीयात पर उनका कब्जा काशत है जबकि सत्यता यह है कि भूमि वादग्रस्त पर वादी/रेस्पोंडेंट का रहा है एवं वर्तमान में भी कब्जा रेस्पोंडेंट का ही है। अपीलांत का भूमि वादग्रस्त पर कभी कब्जा काशत नहीं रहा है ना ही वर्तमान में है। अपीलांत अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय में उनकी साक्ष्य नहीं ली गई है जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट को साक्ष्य के कई अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त उनके द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण उनकी साक्ष्य बंद की जाकर एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तनकीयात कायम की गई है। जिसमें तनकी संख्या 1 व 2 को सिद्ध करने का भार वादी/रेस्पोंडेंट को दिया गया था जिसे वादी द्वारा विधिवत रूप से दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध किया है। प्रतिवादीगण को तनकी संख्या 3 व 4 को सिद्ध करने का भार दिया गया था जिसे प्रतिवादीगण सिद्ध करने में असफल रहे हैं। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सवंत 2015 प्रदर्श 1 एवं जमाबंदी सवंत 2019 से 22 प्रदर्श 3 से भूमि वादी मंदिर की खुदकाशत खातेदारी व कब्जे की होना प्रमाणित हुआ है तथा प्रदर्श 2 जमाबंदी सवंत 2064-67 में अपीलांत/प्रतिवादी नं० 1 के हक में दर्ज खातेदारी इन्द्राज अवैध माने गये हैं। इस प्रकार वादी/रेस्पोंडेंट द्वारा अपने वाद का पूर्णतया सिद्ध किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सम्पूर्ण दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर एवं तनकीयात कायम करते हुए प्रत्येक तनकी पर विधिवत रूप से विवेचन करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांत की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा एवं कायम किये जाने रिसीवर पेश किया गया है। यहाँ यह तथ्य समाचीन है कि किसी भूमि पर रिसीवर कायम कराने हेतु टीनेन्सी एक्ट की धारा 212 (2) के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता है या पक्षकारों के मध्य आपस में फौजदारी होने की स्थिति में एवं जानमाल की गंभीर क्षति होने की संभावना होने की स्थिति में संबंधित थानाधिकारी द्वारा बाद अनुसंधान धारा 145 सी आर पी सी के तहत भूमि को रिसीवर में लेने बाबत इस्तगासा सक्षम न्यायालय में पेश किया जाता है। जब रिसीवरी की कार्यवाही की जा सकती है। हस्तगत प्रकरण में वादी द्वारा घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा व


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

कायम रिसिवरी के बाबत रिलीफ चाही गई है, जबकि रिसीवरी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजीयात का वादी को खातेदार घोषित करते हुए तथा प्रतिवादी/अपीलांट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर भूमि को रिसीवरी में लेने के आदेश पारित किये गये है। जबकि भूमि को रिसीवरी के लिए कानून में अलग से प्रावधान है। भूमि को रिसीवरी में लेने के आदेश ताफैसला दावा तक ही प्रभावी होते है। हस्तगत प्रकरण में दावे में ही भूमि को रिसीवरी में लिये जाने के आदेश दिये गये है। जो कानून के विपरीत है। यदि वादी वादग्रस्त आराजीयात पर रिसीवर नियुक्त कराना चाहता है तो उसको धारा 212 (2) आर एक्ट के माध्यम से चाराजोही करनी चाहिए थी। दावे के माध्यम से भूमि को रिसीवरी में लिया जाना कानून के खिलाफ है। इस कानूनी बिन्दु को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। जो निरस्त योग्य है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है कि प्रकरण में अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे एवं यदि वादी वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त कराना चाहता है तो वह विधि अनुसार टीनेन्सी एक्ट की धारा 212 (2) के प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः अपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, करौली के प्रकरण संख्या 60/10 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.25 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.06.2026 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 28.4.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कान्त बालोत)
राजस्व अपील प्रधिकारी
सवाई माधोपुर